

प्रेषक,
जे०पी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ०६ जुलाई, 2015

विषय:-जनपद ऊधमसिंहनगर में केन्द्र पोषित एम०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्वीकृत आई०टी०आई० कॉलेज, सितारगंज की स्थापना हेतु कुल 1.261 है० भूमि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-982/सात-स०भू०अ०/2015 दि०-08.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद ऊधमसिंहनगर, तहसील सितारगंज, परगना किलपुरी, ग्राम सितारगंज के खा०ख० सं०-641 के खसरा सं०-53 रकबा 0.789 है०, 64/2/2 रकबा 0.316, 64/2/1 रकबा 0.156 है० इस प्रकार कुल 1.261 है०, वर्ग-5(3)ड अन्य बंजर भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दि०-15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभागीय परामर्श/सहमति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

- 8- प्रश्नगत जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0-436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0-जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

पू0प0संख्या-1779 /समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- ✓ 5- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Alok
(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।